

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (चितीडाह)

चीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

प्रकरण संख्या :- 59/2015

दायर दिनांक :- 09.09.2015

निर्णय दिनांक :- 19.04.2024

प्रार्थीगण

पनाम

अप्रार्थीगण

1. कल्याणमल पिता देवीलाल यादव
निवासी - जाशमा
तहसील - भूपालसागर (चितीडाह)

1. दिनेश पिता रुपा यादव
2. प्रभुलाल पिता रुपा यादव
3. नरेन्द्र पिता रुपा यादव
4. अरुण पिता रुपा यादव
5. कमली वार्ड देवा रुपा यादव
6. कंकु वार्ड फकीरपुरी रुपा यादव
7. जीता पुत्री रुपा यादव
निवासीमान - कुंवारीया
तहसील - रेलमगरा (राजमगर)
8. भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर
9. पटवारी प० ह० - जाशमा
तहसील - भूपालसागर (चितीडाह)

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति - श्री नारायणलाल जाट वकील हर्ष
श्री एस के वापना वकील अजमेर
श्री कृष्णचन्द्र तुलझिया वकील हर्ष

* निर्णय *

1942
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला - विसोडाह (राज.)

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त में तदप्रकार है :-

- (1) यह है कि ग्राम जाशमा प० ह० हल्का जाशमा तहसील भूपालसागर हल्के बैरनी में स्थित आ० न० 422 रकबा 0.90 हेक्टर, आ० न० 423 रकबा 1.033 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.933 हेक्टर भूमि स्थित है जिसे आगे वादग्रस्त आराजियात के नाम से अधिष्ठित किया गया है वर्तमान में उक्त आराजियात रुपा पिता देवा यादव के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है लेकिन रुपा की मृत्यु हो जाने से रुपा के विधे



—लगातर—

वारिसान प्रतिप्राची संख्या 1 से लगायत 3 तक बनाये गये हैं।
 (2) यह है कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजियात 60 वर्ष से प्राची के दादा के कब्जे काबत रही है तथा इसके बाद प्राची के पिता देवीमाल उक्त आराजियात पर 40-45 वर्ष पूर्व कृषि कार्य करते रहे हैं। उक्त आराजियात को रुपये लगाकर प्राची के पिता ने ही ऊपजाऊ बनाया है। वादग्रस्त आराजियात पर स्वयं प्राची का 20 वर्षों से कब्जा-काबत है। वादग्रस्त आराजियात पर विगत 60 वर्षों से प्राची के दादा, पिता व स्वयं प्राची का कब्जा चला आ रहा है जबकि किसी भी आराजी पर 12 वर्षों से अधिक समय तक कब्जा होने पर एडवर्स पजेसन के आधार पर उस ट्पाबित का एक अधिकार बन जाता है जो आराजियात पर काबिज होता है। आज तक अप्राचीगण ने प्राची के कब्जेबुदा वादग्रस्त आराजियात पर कोई एक व अधिकार नहीं जताया है ना ही कभी उक्त भूमि पर काबत की है। इस कारण प्राची उक्त आराजियात की खातेदारी की घोषणा कराये जाने का वैधानिक अधिकार रखता है।

(3) यह है कि प्राची के पास वादग्रस्त आराजियात के अलावा ओर कोई कृषि आराजियात नहीं है। प्राची के परिवार का अरण घोषण इसी आराजियात से चलता है। अप्राचीगण सिर्फ राजस्व रेकॉर्ड में भूमि अपने नाम होने से किसी अन्य को विक्रय करना-चाहते हैं जो गलत है। अतः प्राची ने विरुद्ध अप्राचीगण के खिलाफ अस्थायी निवेधाना का आदेश फरमाने बाबत निवेदन इस अमर का किया कि वादग्रस्त आराजियात का किसी भी प्रकार से अप्राचीगण विक्रय, वसीयत, दान कर खुर्द-बुर्द ना करें एवं अन्य किसी प्रकार से मुक्तकिल ना करें। अप्राची संख्या-8 किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन न तो स्वयं करे ना ही किसी अधीनस्थ कर्मचारी, नौकर या एजेन्ट से करावे। अप्राची संख्या-9 किसी भी प्रकार का नामान्तरण उक्त आराजियात संबंधित अर कर फैसल न करावे न ही राजस्व रेकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करावे।



सहायक कलेक्टर एवं
 उपरान्त अधिवारी, मुद्राप्राचीगण
 जिला न्यायालय (क)

इस पर प्राची का प्रार्थना-पत्र दर्ज राजिस्टर कर जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्राची संख्या 1 ता 3 तरफ से वकील श्री कृष्णचन्द्र तुलाधिया ने अपना वकालतनामा व जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया। अप्राची संख्या-1 की तरफ से वकील श्री सुरेश कुमार बापना ने अपना वकालतनामा पेश किया।

— लगातार —

वकील प्रार्थी द्वारा रुपताल तथा रहमान के साथ-पत्र पेश किये गये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल खसरा गिररावरी मौजा जाशमा की संवत् 2049 से 2063 की फोटो प्रति पेश की। नकल भित्ता झीट की फोटो प्रति पेश की गयी। वकील उग्रय पत्र बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि मौजा जाशमा की वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी 60 वर्षों से काबिज है तथा बतने वर्षों से कृषि कार्य भी प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है। इसके उपजाऊ बनाने हेतु 20 वर्ष पूर्व खर्चा भी प्रार्थी द्वारा किया गया। वार से पूर्व अप्रार्थीगण इस आराजियात पर कभी नहीं आये। वादग्रस्त भूमि अभी प्रार्थी द्वारा सिजारे पर दे रखी है। सिजारे का सहमति-पत्र भी प्रार्थी के पास मौजूद है। वार में मौका पर्चा रिपोर्ट संलग्न है। एडवर्स पजेक्शन के आधार पर प्रार्थी काबिज है। पूर्वजों के समय से हम उक्त भूमि पर काबिज है तथा प्रार्थी के परिवार का अरण-चोखण भी उक्त वादग्रस्त आराजियात पर निर्भर है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। आज से पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा इस भूमि बाबत कभी कोई शेरराज जाटिर नहीं किया गया। कच्चा साक्ष्य दस्तावेजों से निर्धारित होगा तब तक अप्रार्थीगण भूमि का बेचान ना कर दे जिस्से अपूरणीय हानि प्रार्थी को होगी। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है तथा लगान भी अप्रार्थीगण अदा कर रहे हैं। प्रार्थी अनाधिकृत रूप से हमारी भूमि में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रार्थी के पास कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है और ना ही उक्त भूमि पर प्रार्थी का कच्चा है। सहमति-पत्र प्रार्थी ने अभी कूटरचित बनवाया है। प्रार्थी ने 2012 से अभी तक कमिश्नर नियुक्त नहीं करवाया है। अप्रार्थीगण ने घाने में भी रिपोर्ट देज करवाई लेकिन निवेद्याता के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। अप्रार्थीगण की भूमि को सिजारे पर देने का कोई अधिकार प्रार्थी को नहीं है। धारा-35 Evidence Act जिसके अनुसार जिसके नाम भूमि राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है वो ही उसका मालिक होगा। खटन (Rebuttal) बहस में वकील प्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थीगण ने 60 वर्षों में कभी भी यह नहीं दोहराया कि हमारी जमीन को सिजारे पर ब्यो दिया है। बहस के साथ ही प्रार्थी वकील ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय "रविन्द्र कोर शेवाल बनाम मंजीत कोर" 03 अगस्त 2019 व "श्री उत्तमचन्द वल्लभ नाथूराम" लगातार




A-14/4/20
 सहायक कलेक्टर एवं
 डी.ओ.ओ., भूपालसिंह
 जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

सिविल अपील नं० 130/2020 (समावृती नं० 15321/2011) के निर्णय की प्रतियाँ पेश की। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी खण्डन (Submittal) बहस में बताया कि अप्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार हैं और श्री निवेद्यता के कारण वह अपनी भूमि का बेचान नहीं कर पा रहे हैं अतः प्राप्ति का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने बहस के साथ दस्तावेजों के रूप में RRT 1995 पैज 613, RRT 2018-19 पैज नं० 69, RRT 2005(2) पैज नं०-1431, RRT 2006(2) पैज नं० 1410-11, RRT 2021(1) पैज नं०-35, 36, RRT 2008(2) पैज नं०-1448-56 पेश किए।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवलीकन किया तथा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अस्थायी निवेद्यता के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय होते व सुविधा का संतुलन प्राप्ति के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं। अप्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार हैं और रिकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निवेद्यता जारी नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण रिकॉर्ड खातेदार होते हुए भी नटे के कारण अपनी भूमि का बेचान इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं अतः अपूरणीय होते प्राप्ति को न होकर अप्रार्थीगण को हो रही है। सुविधा का संतुलन श्री प्राप्ति के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है क्योंकि प्राप्ति रिकॉर्ड खातेदार नहीं हैं। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, वकील उभय पक्ष की बहस के आधार पर प्राप्ति का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काब्रकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल नुमांर होकर नम्बर से कम होकर दायरेल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 13.4.21
सहायक कलेक्टर एवं
मुख्य अधिकारी, भूपालसागर
जिला-बिस्मिलगढ़ (राज.)